SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Madam, I also associate myself with this Special Mention.

THE DEPUTY CHAIRMAN; The House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-four minutes past two of the clock,

[The Vice-Chairman (Shrimati Jay-anti Natarajon) in the Chair]

THE TEA COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF SICK TEA UNITS) AMENDMENT BELL, 1991

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We will now take up dicussion on the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Amendment Bill, 1991.

Mr. Salman Khursheed.

TE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED). Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Act, 1985, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN); It is now open for discussion.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): मेडम वाइसचेयरमैं साहिबा, वजीरे मोहतरम ने जो तरमीम पेश की है उसका मैं हिमायत करता हूं । इसलिए कि इसके सिवा कोई चारा नही है । मुकर्रर वक्त के अन्दर क्लेम्स सब की मिलते नहीं हैं । इसकी वजह से जैसा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा गया है । 1 करोड़ 28 लाख रुपयों से भी ज्यादा के क्लेम्स बाद में जिनमें ज्यादातर मजदूरों का पैसा है । जाहिर है कि यह पैसा उनको मिलना चाहिए । सभी को उनसे हमदर्दी होगी । इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो सवाल उठता है वह यह है कि चार चाय बागान कौमी मिलकियत में लिये गये हैं।

इनको सिक बनाकर जो प्राइवेट मालिकान चले गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? इनको सिक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है, जिन लोगों को क्लेम है । यह पैसा सरकार अपने फंड से देगी । यह अवाम का पैसा है । लेकिन हमारे देश में यह एक अफसोसनाक बात है कि चाय बागान हो या कारखाने प्राइवेट सैक्टर के मालिकान मिस-मैनेजमेंटी की वजह से, करप्शन की वजह से फंड को खुर्दबुर्द करने के बाद उनको सिक बनाकर चले जाते हैं । वे प्राविडेंट फंड का तक रुपया हजम कर जाते हैं, ग्रेचुटी तक नहीं देते हैं। बाद में जिन मामलात में हुकूमत मदाखलत करती है तो उस समय वह उन मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती । इसलिये मेरी पहली तजवीज यह है कि इस सिलसिले में एक जरूरी

कानून ऐसा बनाना चाहिये कि जो असली मालिक हैं, उनकी जो निजी जायदाद है चाहे वह मनकूला हो या गैर-मनकूला हो वह जायदाद जब्त कर ली जाय और कारखाने या चायबागान इनकी सिकनेस जब शुरू होती है तो शुरू में ही उस पर कंट्रोल रखने का इंतजाम किया जाय । ऐसा कैसे होता है कि प्रोविडेंट कमिश्नर मौजूद होता है लेकिन प्रोविडेंट फंड का रुपया जमा नहीं होता है । या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और अगर होती भी है तो अदालत के चक्कर में कई साल बीत जाते हैं । जब अदालत से कोई रकम मुकर्रर की जाती है किश्त-वार तो एक किश्त या दो किश्त अदा करने के बाद मालिक फिर भाग खड़े होते हैं और फिर हालत जैसे की तैसे हो जाती है । चुनाचे मौजूदा कानून इसके लिये एडीक्वेट नहीं हैं और इसके लिये स्ट्रिन्जेंट कानून बनाने की जरूरत है, यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि चाय की पैदावार बढ़ाने के लिए इमकानात काफी मौजूद हैं । महोदया, आप जानते हैं कि हमारा यह मुल्क कुदरत की दौलत से मालामाल है और चाय की पैदावार में बहुत आसानी है । बरसात का पानी जिन पहाड़ी इलाकों से गुजरता है, उनकी तराई में चाय की खेती या चाय बागान लगते हैं । अभी तक बंगाल, असम और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में चाय की पैदावार हो रही है । लेकिन मेरे ख्याल में तो इसके लिये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गुंजाइश है । जहां बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं उनकी तराइयों में रिसर्च का काम करके चाय बागान अगर वहां लगाये जाय तो लाखों लोगों की रोजी उसमें लग सकती है। चाय का इस्तेमाल हमारे देश में भी बढ़ रहा है और सारी दुनिया में भी बढ़ रहा है। एक जमाना था जब कि चाय का एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान का मुकाम पहला था। किंतु आज हमारी यह पोजिशन नहीं है । हम पीछे छूट गए हैं और हमारी जगह श्रीलंका ने ले ली है । एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ नहीं रहा है । अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़े तो इससे गैर मुल्की जरेमुबादला मिलता है । उसको हम बढा सकते हैं जो कि हमारे कौमी माशियत के लिए इंतिहाई जरूरी है । इसके अलावा चाय की क्वालिटी भी बेहतर बनानी चाहिए । मैं कुछ दिनों पहले चीन गया था । चीन में मुझे दिखाया गया चाय का एक बाग और यह बताया गया कि इसमें जो चाय पैदा होती है उसकी कीमत एक हजार रुपए फी किलोग्राम है । उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और रंग भी अच्छा आता है । उन्होंने इसके लिए ऐसा इंतजाम किया है ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर बने । चुनाचे हमारे यहां भी अगर मिट्टी और पानी के साथ साइंस और टैक्नालाजी का इस्तेमाल किया जाए तो चाय की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है और इसकी पैदावार भी बढ सकती है । इसलिए इस सिलसिले में रिसर्च के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए । यहां चाय के जो कारखाने चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर कारखानों में, जहां तक मेरी इन्फार्मेशन है, मशीनें पुरानी हैं, जिद्दतकारी के काम पर ज्यादा तवज्जह नहीं दी जा रही है । जो कारखाने, सिक हो जाते हैं उनकी भी एक यही वजह है कि पुरानी मशीनें हैं और

[श्री मोहम्मद अमीन]

कंपीटिशन की वजह से वे बाजार में खड़े नहीं हो पाते हैं। चुनाचे अगर हुकूमत चाहती है, इससे हुकूमत को भी काफी आमदनी हो सकती है तो उस आमदनी का एक हिस्सा अगर जिद्दत-तकारी पर खर्च किया जाय तो इससे चाय की पैदावार भी बढ़ सकती हैं और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती हैं।

इसके साथ ही चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो मगरबी बंगाल का रहने वाला हूं और मगरबी बंगाल में चाय की पैदावार बहुत होती है, बहुत सारे चाय बागान हैं। वहां चूंकि मजदूरों की ट्रेड यूनियन तहरीक है, इसलिए मजदूरों का मयारे जिन्दगी काफी हद तक बेहतर है। जो कम से कम सहूलियतें उनको मिलनी चाहिए वह मिलती हैं। मैं यह नहीं कहता कि हालत बिलकुल इत्मीनानबक्स है और भी कुछ करने की जरूरत है लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों की बनिस्बत मगरबी बंगाल में ट्रेड यूनियन तहरीक मजबूत होने से चाय बागान मजदूरों की हालत कुछ बेहतर है मगर बाकी जगहों में जो अफसोसनाक हालात है वह यह है कि मजदूरों को इन्सान की तरह कम से कम सहूलियतें जो मिलनी चाहिए वह मयस्सर नहीं हैं। न रहने के लिए मुनासिब घर हैं, न बिजली है। कहीं कहीं तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है। उनको दूरदराज के कुओं से पानी लाकर के इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राइवेट मालिकान सुबह से लेकर शाम तक उनसे काम कराते हैं। तनख्वाह भी कम देते हैं। यहां तक जो तनख्वाहें मुकर्रर हैं वह भी नहीं दी जाती हैं। उन से अंगूठा लगवा कर गुन्डों के जोर से, दलालों के जरिए कम पैसा दे कर के उनको हटा दिया जाता है। चाय बागान में जहां औरतें काम करती हैं, उनकी हालत और ज्यादा अफसोसनाक है। काम करने वाली औरतों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती, होती है। इसके साथ ही यह बात भी है कि उनको पैसा कम मिलता है यानी एक ही काम के लिए मर्द मजदूरों को जो तनख्वाह मिलती है वह औरत मजदूरों को न मिलती है हालांकि इस बात को सब लोग तसलीम करते हैं कि चाय की पत्तियां तोड़ने का काम औरत बेहतर करती है। नर्म अंगुलियों की जगह से वह चाय के लिए ज्यादा बेहतर होती हैं। उनका उसी तरह एहतराम भी किया जाना चाहिए। मगर अफ़सोस की बात है कि वह नहीं होता। कमसिन बच्चों को काम पर लगाया जाता है। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, वह सुबह से शाम तक चाय बागान में काम करते हैं। उनको लिखना-पढना आता नहीं है। सामाजिक तौर पर वह पसमांदा रह गए हैं। ऐसी भी मिसालें आपको मिलेंगी जिनके बाप-दादा चाय के बागान में काम करते थे, दो नस्ल, तीन नस्ल गुजर जाने के बाद भी उनके बच्चे भी वहां काम करते हैं, अनपढ़ रह गए हैं और उनकी जिन्दगी में कोई तबदीली नहीं आई हालांकि मुल्क को आजाद हुए 45-46 साल हो गए हैं। इसके अलावा मेरी जो आखिरी बात है वह यह है कि इस कानून में तरमीम

जरूर की जाए और जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, हुकूमत इन पर अच्छी तरह गौर करे। गौर करने के बाद मजदूरों के लिए जो कुछ भी कदम सरकार उठाएगी मजदूर ट्रेड युनियन तहरीकों का पूरा ताव्वुन उनको मिलेगा। अगर सब का ताव्वुन हासिल किया जा सका तो चाय की सनद हिन्दुस्तान में तरक्की कर सकती है। इससे जो लोग चाय की सनद में लगे हुए हैं उनका भी भला होगा और पूरे देश का भला होगा। इतना ही मुझे कहना है। शुक्रिया।

شری محمد امین انصاری بنگال ... میڈم وائس چیئرمین صاحبہ، وزیر محترم نے جو ترمیم پیش کی ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے مقررہ وقت کے اندر سکیم سب کو ملتی ہیں اس کی وجہ سے جیسا کہ [illegible] ایجیٹیشن [illegible] کہا گیا [illegible] ایک کروڑ ۴۰ لاکھ [illegible] کے کلیمس بعد [illegible] ہیں جن [illegible] مزدوروں کا پیسہ [illegible] ہے کہ یہ پیسہ ان کو ملنا چاہئے [illegible] سے بہتری ہوگی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اس سلسلے میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ چار چائے باغان قومی ملکیت میں لئے گئے ہیں ان کو سِک بنا کر جو پرائیویٹ مالکان چلے گئے ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔ ان کو سِک بنانے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے۔ جن لوگوں پر کلیم ہے۔ یہ پیسہ سرکار اپنے فنڈ سے دے گی یہ عوام کا پیسہ ہے لیکن ہمارے دیش میں یہ ایک افسوسناک بات ہو گئی ہے چائے باغان ہوں یا کارخانے پرائیویٹ سیکٹر کے مالکان مس مینجمنٹ کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے فنڈ کو خرد برد کرنے کے بعد سِک بنا کر چلے جاتے ہیں وہ پراویڈنٹ فنڈ تک کا روپیہ ہضم کر جاتے ہیں۔ [illegible] نہیں دیتے ہیں بعض میں جن معاملات میں حکومت مداخلت کرتی ہے تو اس سے وہ ان مالکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے۔ اس لئے میری پہلی تجویز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک ضروری قانون آنا چاہئے چاہئے کہ جو اصلی مالک رہے ان کی جو بھی جائداد ہے چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ جائداد ضبط کر لی جائے اور کارخانے یا چائے باغان ان کی سکنیس جب شروع ہوتی ہیں تو شروع میں ہی اس پر کنٹرول رکھنے کا انتظام کیا جائے ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پراویڈنٹ کمشنر موجود ہوتا ہے لیکن پراویڈنٹ فنڈ کا روپیہ جمع نہیں ہوتا ہے یا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی

†[ ]Transliteration in Arabic Script

نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو آمدنی کے چکر میں کئی سال بیت جاتے ہیں۔ جب عدالت سے کوئی رقم مقرر کی جاتی ہے قسط وار تو ایک قسط یا دو قسط ادا کرنے کے بعد مالک پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر حالت جیسے کی تیسے ہو جاتی ہے چنانچہ موجودہ قانون اس کے لئے ایڈی کوئیٹ نہیں ہے اور اس کے لئے "اسٹرنجینٹ" قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ میری پہلی بات ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چائے کی پیداوار بڑھانے کے لئے امکانات کافی موجود ہیں۔ مہودیہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک قدرت کی دولت سے مالا مال ہے اور چائے کی پیداوار میں بہت آسانی ہے۔ برسات کا پانی جن پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے۔ ان کی ترائی میں چائے کی کھیتی یا چائے کے باغات لگتے ہیں ابھی تک بنگال۔ آسام اور جنوبی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں چائے کی پیداوار ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تو اس کے لئے اتر پردیش میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ جہاں بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں ان کی ترائیوں میں ریسرچ کا کام کرکے چائے باغان وہاں لگائے جائیں تو لاکھوں لوگوں کو روزی اس میں لگ سکتی ہے۔ چائے کا استعمال ہمارے دیش میں بھی بڑھا ہے اور ساری دنیا میں بھی بڑھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب چائے کا ایکسپورٹ کرنے میں ہندوستان کا مقام پہلا تھا لیکن آج ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہماری جگہ سری لنکا نے لے لی ہے۔ ایکسپورٹ بھی ہمارا بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر ہمارا ایکسپورٹ بڑھے تو اس سے غیر ملکی زرمبادلہ ملتا ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں جو کہ ہماری قومی معیشت کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چائے کی کوالٹی بھی بہتر بنانی چاہئے۔ میں کچھ دنوں پہلے چین گیا تھا۔ چین میں مجھے دکھایا گیا چائے کا ایک باغ اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جو چائے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی قیمت ایک ہزار روپیہ کلوگرام ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور رنگ بھی اچھا آتا ہے۔ انہوں نے اس کے لئے ایسا انتظام کیا ہے تاکہ اس کی کوالٹی بہتر بنے۔ چنانچہ اگر ہمارے یہاں بھی مٹی اور پانی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو چائے کی کوالٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور اس کی پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس لئے اس سلسلے میں ریسرچ

ملک کے دیگر حصّوں کی نسبت...
مغربی بنگال میں ٹریڈ یونین تحریک مضبوط
ہونے سے چائے باغات کے مزدوروں کی
حالت کچھ بہتر ہے مگر باقی جگہوں پر جو
افسوسناک حالت ہے وہ یہ ہے کہ مزدوروں
کو انسان کی طرح جو کم سے کم سہولتیں ملنی
چاہئیں وہ میسّر نہیں ہیں۔ نہ رہنے کیلئے
مناسب گھر ہیں نہ بجلی ہے۔ کہیں کہیں تو
پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے۔ ان کو دور
دراز کے کنوؤں سے پانی لاکر کے وہاں
استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پرائیویٹ مالکان
صبح سے لے کر کے شام تک ان سے کام
کرواتے ہیں۔ تنخواہ بھی کم دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ جو تنخواہیں مقرر ہیں وہ بھی
نہیں دی جاتی ہیں۔ ان سے انگوٹھا لگوا کر
غنڈوں کے زور سے دلالوں کے ذریعہ
کم پیسہ دے کر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے
چائے باغات میں جہاں عورتیں کام کرتی
ہیں ان کی حالت اور زیادہ افسوسناک
ہے۔ کام کرنے والی عورتوں کے مسائل ہیں
ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے
اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ان کو
پیسہ کم ملتا ہے یعنی ایک ہی کام کے لئے
مرد مزدوروں کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ
عورت مزدوروں کو نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ

کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیئے یہاں
چائے کے جو کارخانے چل رہے ہیں ان میں
زیادہ تر کارخانوں میں جہاں تک میری
انفارمیشن ہے مشینیں پرانی ہیں جدّت کاری
کے کام پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے
جو کارخانے سک ہو جاتے ہیں ان کی بھی
ایک یہی وجہ ہے کہ پرانی مشینیں ہیں اور
کمپیٹیشن کی وجہ سے وہ بازار میں کھڑے
نہیں ہو پاتے ہیں۔ چنانچہ اگر حکومت چاہتی
ہے تو اس سے حکومت کو بھی کافی آمدنی
ہو سکتی ہے تو اس آمدنی کا ایک حصہ جدت کاری
پر خرچ کیا جائے تو اس سے چائے کی
پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے اور اس کی کوالٹی
بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چائے
باغان میں کام کرنے والے مزدوروں کے لئے
دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں تو
مغربی بنگال کا رہنے والا ہوں اور مغربی
بنگال میں چائے کی پیداوار بہت ہوتی
ہے۔ بہت سارے چائے کے باغات ہیں
وہاں کیونکہ مزدوروں کی ٹریڈ یونین
تحریک ہے۔ اس لئے مزدوروں کا معیار
زندگی کافی حد تک بہتر ہے جو کم سے کم
سہولتیں ان کو ملنی چاہئیں وہ ملتی ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بالکل اطمینان بخش
ہیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے

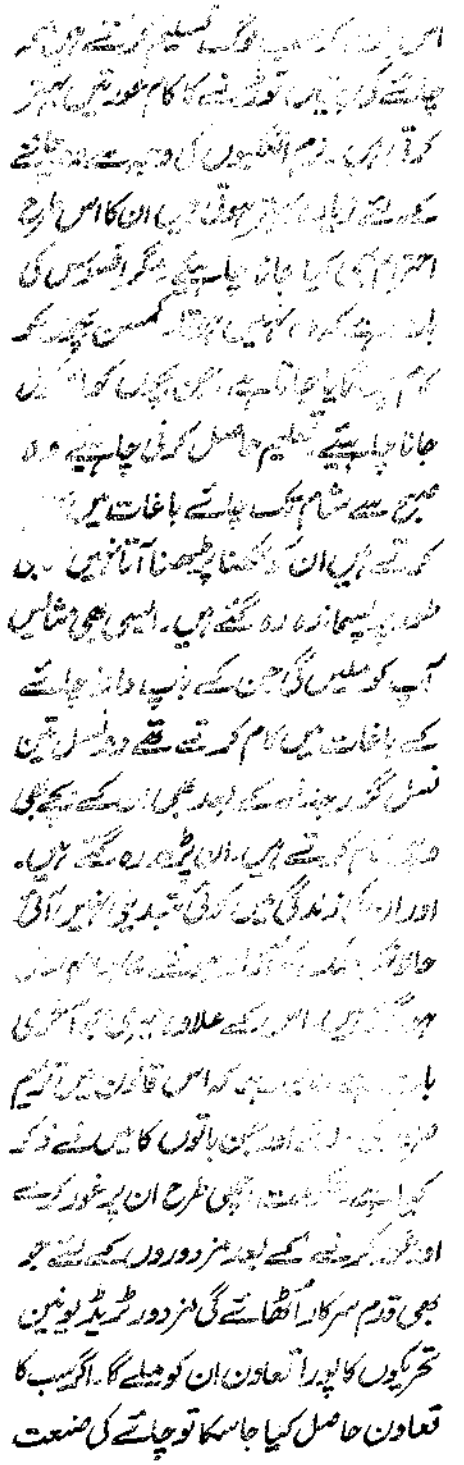

[illegible] لوگ تعلیم [illegible]
چاہئے [illegible] تو ان کا کام محنت [illegible]
کرتے ہیں [illegible] ان کی وجہ سے [illegible]
[illegible] ہوتے ہیں ان کا اس [illegible]
[illegible] کیا جانا چاہئے مگر افسوس کی
[illegible] کمسن بچوں کے
[illegible]
جانا چاہئے تعلیم حاصل کرنا چاہئے [illegible]
[illegible] لوگ چائے باغات میں [illegible]
کرتے ہیں ان [illegible] پڑھنا آتا نہیں [illegible]
[illegible] پسماندہ رہ گئے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں
آپ کو ملیں گی [illegible] چائے
کے باغات میں کام کرتے تھے [illegible]
[illegible] ان کے بچے بھی
[illegible] کرتے ہیں ان پڑھ رہ گئے ہیں۔
اور [illegible] زندگی [illegible]
[illegible]
[illegible] اس کے علاوہ [illegible]
بات [illegible] کہ اس قانون [illegible]
[illegible] باتوں کا [illegible]
کیا [illegible] اسی طرح ان پر غور کرتے
اور [illegible] کے بعد مزدوروں کے لئے جو
بھی قدم سرکار اٹھائے گی مزدور ٹریڈ یونین
تحریکوں کا پورا تعاون ان کو ملے گا۔ اگر سب کا
تعاون حاصل کیا جا سکا تو چائے کی صنعت
ہندوستان میں ترقی کر سکتی ہے۔ اس سے
جو لوگ چائے کی صنعت میں لگے ہوئے
ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا اور پورے دیش
کا بھلا ہوگا اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔ شکریہ
(ختم شد)

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa) Madam Vice-Chairmian, I would like to support the Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Amendment Bill, 1991. It is a very simple Bill, in the Act of 1985, a provision was made to appoint a Commissioner to look into the claims of different employees of the sick units which were nationalised. But unfortunately in the Statement of Objects and Reasons, it has been pointed out that more than 3000 claims were not presented in time. This Bill has been brought forward to enable the Government to pay compensation for 3000 claimants. They can have their legitimate claims. So there is no controversial thing In this Bill. Therefore, I want to support this Bill. But the only question the nation would like to know is whether the cut-off date is 20th April, 1989 for presenting the claims petition by the TTCL. But they presented it in July, two months later. I would like to know whether they received the claim in time or whether there was difficulty even in prsenting a claim to the Commissioner. Or was it because of any disturbance or difficulty there that the claims could not be presented in time? We want to have an explanation before amending the provisions. This is one of the particular questions I would like to raise.

The second point is, the earlier Act of 1985 speaks of the acquisition and nationalisation of sick units. Now the hon. Minister also tells us that there are 145 sick units. I want to know, through you, Madam, from the

hon. Minister what plans they have to make these sick units produce more and whether they have any plans of taking over sick units or amalgamating them with units of better management.

Now, I come to the bigger question which is facing the county in respect of tea. That is whether, by the end of the Century, the common man can get the golden beverage of a cup of tea from our own production or depend on imported tea. This is a fundamental question. If we see the RBl report, we find that the an. nual growth of consumption of tea from 1977 to 1988 has been 4.8 per cent whereas the growth of tea production has been only three odd per cent. So it is very doubtful whe. ther in future we will he able to have sufficient production in the country to meet our own domestic needs, not to speak of export. Till some years back, we were the leader exporters of tea in the world. Our share in the world market in the 70s was roughly 35 per cent. Now it has come down to 15 per cent and to the staggering figure of 200 million Kgs. The basic question is two-fold; commercial production, that is, quan. tity of production and quality of production. To be the leader of the export market in the whole world, as we were earlier, we have to concentrate on both. At the same time, we cannot forget the fact that the only thing that the common man in the country enioys today is a cup of tea which is the beverage of the poor man in the country And that must be guaranteed to him For that we have. to take certain bold steps. We have to go into the fundamental question of why production is not growing. In my opinion, it is mainly due to lack of improvement in the plantations and the productivity.

I would like to make certain suggestions in order that production may improve. There must be a national survey of different areas where tea has not hitherto been planted. We have to bring more areas under tea.

cultivation so that the level of pro duction may go up. Today the pro duction is expected to be 730 million. Kgs. But by the end of the Century, we must take bold steps to reach at least one million Kgs. more or two million Kgs. more. That requires a bigger projection, We must try to emphasise those areas where tea was not planted earlier. Those areas must be served now. In those areas, incentives must be given for growing tea plantations. I am happy that the Government of India has taken up 2500 hectares in Nilgiri Hills. But it is not sufficient. It is necessary that some other areas are also taken in. Even in my State, Orissa a sur vey was made. It has been shown by that survey that this is feasible in Keonjhar, Phulbani and Mayurbh. anj Districts of the State of Orissa. Some beginning has been made in Keonjhar and tea has been harvested and it is of higher quality. We are facing international competition in the market from Ceylon, China, Ken ya and other countries. They are giving a lot of stress on the growth of tea plantations in their countries. If we want to survive as a leading exporter in the world and meet our domestic requirements also, we have to take bold steps. We have to take in new additional areas for plantation of tea wherever it is feasible— When we talk of growing more. we should bear in mind the fact that there is scarcity of land too. Here, the fundamental point is, we have to organise better marketng for small growers of tea so that we do not require a big stretch of 3000 hectares at one stretch of area, which will not be available in many places. We know in many hilly areas. 3.00p.m.there are a number of valleys which can be utililised for the purpose of tea plantation. The Government must pay proper attention to this fact. Secondly there must be concerted efforts for the growth of better quality tea in our country, as has been pointed out by the earlier speaker and for:

[Shri Santosh Kumar Sahuj

that, we must have proper research, proper publicity and the necessary-infrastructure. Thirdly, if we want to lead in the world in tea production then quality tea blending is a most important question to which we must address ourselves.

It is not proper for us to import tea into this country and then to blend it in India. If we do so, the country will have to suffer a lot. The tea so prepared would be very costly. At the same time, it will affect our commercial plantation programme. We must take steps to ensure that our productivity of tea must increase qualitatively in additional areas. In order to achieve the same, the organisation which is looking after this, must see that our production of tea increases and that we try our level best to achieve the position which we once had enjoyed in this field in the international market.

Another important question is, the management must improve. The pli ght of labourers in tea plantation is very bad. The Government must take immediate steps to improve their lot by providing them good working conditions, good wages and all that. Unless it is done, the production can not increase. The participation of labourers in the management is very important. The Government must be framing laws for improving' the Jot of the labourers; The Government must lay emphasis on this aspect in the New Economic Policy. They cannot be neglected for long. The New Economic Policy must be followed with a new social outlook in respect of tea plantation workers where the exploitation is at its height. This problem requires our immediate attention.

Then the procedure of blending must be improved. We were the leader once in the world. We must see that good quality tea is readily available. The hon. Minister might be knowing that good quality tea is not available in the domestic market. Sometimes it is very rarely available in the market. But the citizens of this country must also get good quality tea for their consumption. There is a huge demand for it. We must take care of our export but at the same time, we must make it available for our domestic consumption also because tea is a common beverage which the people of this country want to enjoy at any time.

This is a small, innocuous Bill, for providing more benefits to the people in this field. I support this Bill with a request to the hon. Minister that 'at least more areas to produce 2 million more in coming years should be brought under tea plantation so that we can guarantee good quality of tea to our people and they will not have to depend on imported tea which is very costly and the poor people cannot afford to buy the same. With these words, I conclude. Thank you.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, जो बिल वजीरे तिजारत ने पेश किया है, मैं इसकी ताईद और हिमायत करता हूं और उसकी सब से बड़ी वजह यह है कि जैसा कि इस बिल में बताया गया है कि जो पैसा, एक करोड़ अठाईस लाख रुपया क्लेम का मज़ीद देने का इरादा है, उसका ज्यादातर हिस्सा बर्किंग क्लास को जाने वाला है। इसलिए इस बिल के पास होने में तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सब तरफ से इसको हिमायत मिलेगी। लेकिन आज जब यह बिल आया है तो चाय की सन्नत जो हमारे हिन्दुस्तान की एक बहुत ही अहम तारीखी और पुरानी सन्नत है, उसकी जो मौजूदा हालत है उस पर तवज्जह भी जरूर देनी चाहिए और उसका जिक्र भी इस मौअज्जिज एवान में जरूर होना चाहिए ।

मैडम, हिन्दुस्तान में जो चाय पैदा होती है, खास तौर पर अपर आसाम के इलाकों में जो चाय पैदा होती है, वह चाय पूरी दुनिया में न सिर्फ मशहूर है बल्कि कहा जाता है कि दुनिया में

उससे अच्छी चाय कहीं पैदा नहीं होती। लेकिन अफसोस का मकाम है या हमारे मुल्क की यह बदकिस्मती है कि हमारी जो भी ऐसी सन्नते हैं वह आहिस्ता-आहिस्ता किसी न किसी तखरीबकारी की नज़र होती चली जा रही हैं और उससे मुल्क को, मुल्क की तिजारत को, मुल्क के मआशी सूरत-ए-हाल को काफी शदीद नुकसान पहुंचता है। मैडम, हिन्दुस्तान जितनी चाय पैदा करता है उसका तकरीबन 65 फीसदी हिस्सा हम सोवियत यूनियन में एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वहां जो हालात पैदा हुए और वहां जिस तरह से डिस्टरबैंस हुआ उससे गुजिश्ता एक साल में हमारी चाय की सन्नत पर भी उसका काफी बुरा असर पड़ा है और इस एक्सपोर्ट में बड़ी नुमायां कमी वाकए हुई है। अब हम और भी दूसरे मुमालिक को चाय देते हैं। मिसाल के लिए हम ईरान को भी चाय बेचते हैं और इन बहुत सी जगहों पर चाय बेच रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे मौअज़िज़ मैम्बर अमीन साहब ने फर्माया कि हमारा चाय की सन्नत में पहले पहला नंबर था और अब हम अपने से भी बहुत छोटे मुल्क श्रीलंका से भी पीछे आ गए हैं और दूसरे नम्बर पर आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि मौजूदा वजीरे तिजारत को वह तमाम आस्पेक्टस देखने चाहिए जिनकी वजह से हमारी इस तिजारत में कमी वाकए हो रही है। हमारा एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, मुकम्मल तौर पर वह चाय इंपोर्ट करता है। उनके वहां चाय की पैदावार न होने के बराबर है। लेकिन हमारे और उनके दरम्यान बहुत सी तिजारतें जहां जारी हैं वहां चाय की एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन है। मैं समझता हूं कि तिजारत सियासी ताल्लुकात जो हैं वह अपनी जगह चाहे वह टैंस ही क्यों न हों, अपनी जगह रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें तिजारती रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपनी चाय बहुत दूर ले जाकर बेचने के बजाय पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वह श्रीलंका से सारी चाय खरीदते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट में जो कमी आई है उसको हम न सिर्फ यह कि बढ़ा सकते हैं बल्कि हमारे ज़रें मुबादला पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है उसको भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यह तो हमारा बाहर का दृष्टिकोण है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम किस प्राब्लम का शिकार हैं जरा सा उसका भी जिक्र हो जाए तो अच्छा होगा। आसाम में और खास तौर पर अपर आसाम में जिस तरह की तहरीकें चल रही हैं आप उन्हें अलाहदगीपसंद की तहरीकें कह लें, इंतहापसंदों की तहरीकें कह लें, बोडो लैंड या उल्फा के नाम से तहरीकें चल रही हैं उससे बिला शुबहा चाय की सन्नत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हमारे मौअज़िज़ मैम्बर अमीन साहब ने फर्माया कि लेबर की हालत बहुत खराब है यह तो बहुत पुरानी कहानी है। जब तक यह सिस्टम मौजूद रहेगा इस मुल्क में क्या, किसी भी मुल्क के अन्दर जब तक सरमायादार और वर्किंग क्लास रहेगी, हमें यह शिकायत रहेगी। चाहे वह गुजरात की इंडस्ट्री हो, चाहे वह आसाम के चाय के बागान हों या उत्तर प्रदेश की जमीनों पर काम करने वाले मज़दूर हों, यह मसला तो अपनी जगह पर है। उनकी हालत खराब है और औरतों से काम लिया जाता है, बच्चों से काम लिया जाता है। लेकिन एक बहुत अहम बात कि आखिर आज़ यह शिकायत क्यों पैदा हुई? क्योंकि बहुत से बाहर के सरमाएदार आए आसाम के अंदर उन्होंने बागान खरीदे, उनसे प्रोफिट कमाया, करोड़ों-अरबों रुपया कमाया, लेकिन उस उसी जगह इनवेस्ट करने के बजाय, उस काम को और बढ़ाने के बजाय, वह वहां के प्रोफिट का शरमाया निकालकर दूसरी जगहों पर ले गए और वहां लगा दिया। इस मुल्क में किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का हक है कि वह मुल्क के किसी भी हिस्से में जाकर तिजारत करे, लेकिन बिला-शबा इस बात की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वह तिजारत के नाम पर एक्सप्लायटेशन करे। यह आसाम के अंदर होता रहा है।

[श्री मोहम्मद अफजल]

मैडम, हमारा टार्गेट 750 मिलियन किलोग्राम का इस साल का है । मगर हम इसे प्रोडक्शनवाइज देखें तो हम कम-से-कम 9–10 फीसदी कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और उसी की वजह यह है कि इसके साथ सिर्फ प्रोडक्शन ही कम नहीं हो रहा बल्कि क्वालिटी भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें गिरावट आ रही है और वह इसलिए आ रही है कि मैनेजमेंट जो अमूमन बाहर का है, वह इंटीरियर इलाकों में जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, खतरा महसूस कर रहा है सेक्यूरिटी के कारण और जो सस्ती लेबर है वह प्रोडक्शन को उस तरीके से नहीं कर पाती तो एक्सपर्टाइज की जरुरत है, वह उसमें इस्तेमाल नहीं हो पाती है। इसका नतीजा है कि जिस वक्त पत्ती को तोड़ना चाहिए उसके तीन दिन बाद वह टूटती है और चाय की क्वालिटी में फर्क पैदा हो जाता है । उसको जिस तरह ब्लैक करना चाहिए, वह नहीं हो पाता जिसके नतीजे में क्वालिटी गिर जाती है और होता यह है कि एक किलोग्राम चाय पर क्वालिटी गिरने की वजह से कभी-कभी 5 रुपए से 15 रुपये तक का फर्क पड़ जाता है और करोड़ों रुपए का नुकसान इससे होता है ।

मैडम, गुजिस्तां साल आसाम में सुरेन्द्र पाल जो कि स्वराज पाल के भाई थे, उनका दिसंबर में कत्ल हुआ और उसके बाद लिपटन और जो दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने रातों-रात अपने स्टाफ को एअर लिफ्ट किया । अब वहां कोई जाने को तैयार नहीं है । जाहिर है कि जब मैनेजमेंट की जो दिलचस्पी है, वहां कम होती चली जाएगी तो इसका बुरा असर पड़ेगा । मैडम, मुझे खतरा है कल यहां जिस तरह जिक्र हो रहा था तब भी यह बात सामने आयी थी कि जिस तरह पंजाब से लोग वहां की सेक्यूरिटी की प्रॉब्लम की वजह से अपना सरमाया निकालकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में ले जा रहे हैं जिसके नतीजे में पंजाब की जो माशी हालत है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है बिल्कुल इसी तरह से पूरा अंदेशा है कि अगर आसाम के हालत पर काबू पाने की कोशिश नहीं की गयी तो चाय के बागान में जो लोग पैसा इनवेस्ट किए हुए हैं, वह यकीनन वहां से पैसा निकालकर और दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करेंगे और औने-पौने इन बागान और इंडस्ट्री को बेचने की कोशिश करेंगे ।

मैडम, ये इल्जाम लगाया जाता है, हुकूमत इस बारे में ज्यादा बेहतर जानती होगी, कि गुजिस्तां कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर टी एस्टेट्स के जो मालिकान हैं, उनको बाकायदा धमकी दी गयी और 2 लाख से 15 लाख, 20 लाख तक जमा कराने की एक मखसूस जमात के लोगों को कहा गया और बेस्तर लोगों ने पैसा जमा भी कराया ताकि वह अपना कारोबार कर सकें, लेकिन यह टू दे प्रोसेस है । इसमें खाली लेबर का ही मसला नहीं है, मालिकान का भी मसला है । जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए जाता है तो हमें बिल्कुल इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि वह सिर्फ लूट-खसोट करने ही जा रहा है । जब वह अपना सरमाया निकालकर ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज सिक होती है या दूसरे तरीकों से वह सिक बना देते हैं तो अल्टीमेटली उसका नुकसान हुकूमत और मुल्क को उठाना पड़ता है जैसाकि अभी 4 कंपनीज को हुकूमत को लेना पड़ा सिक इंडस्ट्रीज होने की वजह से और इस सिलसिले में एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ी । मैडम, अभी अमीन साहब ने बड़ा सही सवाल उठाया कि आपने सिक इंडस्ट्री डिक्लेअर तो कर दी लेकिन उनको सजा क्या मुकर्रर की ? सजा तो आप कुछ मुकर्रर करते नहीं हैं।

मैडम, इस प्रॉब्लम पर कोई बहुत खास तौर पर तो मेरे पास सुझाव नहीं हैं, लेकिन जो मोटे-मोटे सुझाव मेरे जेहन में आते हैं, वह मैं मोहतरम् वजीरे तिजारात के सामने रखना चाहता हूं ताकि वे उस पर तवज्जो फरमाएं और यह देखें कि चाय के एक्सपोर्ट को हम किस तरह बढ़ा सकें, चाय के प्रोडक्शन को हम किस तरह बढ़ा सकें । न सिर्फ चाय की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ा सकें बल्कि उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकें । मेरा ख्याल है कि आसाम में जो हालात पैदा हो गए हैं खासतौर से, चूंकि बहुत

बड़ी तादाद में हम चाय वहां पैदा करते हैं, वहां यह अहसास डवलप हो गया है आसामी आवाम के दरमियान कि बाहर के लोग यहां आते हैं, हमारे चाय के बागानों से चाय निकालकर ले जाते हैं और प्रोफिट खुद कमाकर दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरुरत इस बात की है कि पार्टिसिपेशन मेनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए तभी यह कुछ थोड़ी सी नफरत कम हो सकती है। मैं जानता हूं, चाय के कुछ मालिकान हैं, जो डरते हैं। कई बार लेबर सही काम नहीं करती और वह उनसे काम भी नहीं ले पाते। इसलिए, कि वह उनसे डरते हैं कि लेबर के किसी लीडर का ताल्लुक वहां किसी अनैतिक-पसंद तहरीक से तो नहीं है, किसी इन्तिहापसंद तहरीक से तो नहीं है। कंट्रोल होना चाहिए लेबर पर मेनेजमेंट का, जो खतम हो गया है, वहीं लेबर का भी मेनेजमेंट पर से एतबार उठ गया है। तो जरुरत इस बात की है कि चाय की सनअत को बेहतर बनाने के लिए लेबर और मेनेजमेंट का एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए, जिसमें लेबर यह महसूस करे कि उसका पार्टिसिपेशन है, चाहे कोपरेटिव के जरिए से किया जाए या और किसी तरीके से ढूंढा जाए। लेकिन, जब तक लेबर का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा उनकी हालत दुरुस्त नहीं होगी, उनका यह अहसास जो बड़ी हद तक सही अहसास है कि दूसरे लोग आकर के यहां से निकालकर के ले जाते हैं, कम नहीं होगा। आसाम का मसला सिर्फ चाय की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, गैर-मुलकियों का मसला भी यहां पर बहुत बार उठता रहा है और यह अहसास डवलप होता रहा है। ...(समय की घंटी)...

दूसरा, मैं आपकी मार्फत यह कहूंगा वजीरे तिजारत से कि एक्सपोर्ट के मामले में नए दरवाजे खोलने चाहिएं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे और कोई मुल्क हो, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनका डिस्टेन्स हमारे यहां से कम है, वहां हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहां ज्यादा से ज्यादा अपने उत्पादन को बेच सकें, ज्यादा से ज्यादा उनको अपना उत्पादन दे सकें। इससे हमारे रिलेशन भी बढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि एक तरह से प्रेसर भी हमारा कायम होता है।

इन अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इस बिल की हिमायत करता हूं और नौजवान जो हमारे वजीरे तिजारत हैं, जो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, उनसे मैं कहूंगा कि कुछ वाकई करके दिखाएं इसके अंदर ताकि हम लोग महसूस करें कि आप आए हैं और आपके पार्टिसिपेशन से कुछ फायदा पहुंचा है। शुक्रिया।

†شری محمد افضل عرف میم افضل (اتر پردیش): میڈم، جو بل وزیر تجارت نے پیش کیا ہے میں اس کی تائید اور حمایت کرتا ہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس بل میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپیہ ٹکیم کو مزید دینے کا ارادہ ہے اس کا زیادہ تر حصہ ورکنگ کیپٹل کو جانے والا ہے۔ اس لئے اس بل کے پاس ہونے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیئے سب طرف سے اس کو حمایت ملے گی۔ لیکن آج جب یہ بل آیا ہے تو چائے کی صنعت جو ہے ہندوستان کی ایک بہت ہی اہم تاریخی اور پرانی صنعت ہے اس کی جو موجودہ حالت ہے اس پر توجہ بھی ضرور دینی چاہیئے اور اس کا ذکر بھی اس معزز ہاؤس میں ضرور ہونا چاہیئے۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

اب ہم اپنے سے بھی بہت چھوٹے ملک سری لنکا سے بھی پیچھے آ گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ وزیر تجارت کو وہ تمام اسپیکٹس دیکھنے چاہئیں جن کی وجہ سے ہماری اس تجارت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک پڑوسی ملک پاکستان ہے۔ مکمل طور پر چائے امپورٹ کرتا ہے۔ ان کے وہاں چائے کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ہمارے اور ان کے درمیان بہت سی تجارتیں جاری ہیں وہاں چائے کی ایکسپورٹ بالکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تجارت سیاسی تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ چاہے وہ ٹینس ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی جگہ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں تجارتی رشتوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیئے اگر ہم اپنی چائے بہت دور سے جا کر بیچنے کے بجائے پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ وہ سری لنکا سے ساری چائے خریدتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ میں جو کمی آئی ہے اس کو ہم نہ صرف یہ کہ بڑھا سکتے ہیں بلکہ ہمارے زرمبادلہ پر بھی اس کا بُرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا باہر کا رشتہ کون ہے

میڈم۔ ہندوستان میں جو چائے پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر آسام کے علاقوں میں جو چائے پیدا ہوتی وہ چائے پوری دنیا میں نہ صرف مشہور ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی چائے کہیں پیدا نہیں ہوتی لیکن افسوس کا مقام ہے یا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو بھی ایسی صنعتیں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی تخریب کاری کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس سے ملک کو۔ ملک کی تجارت کو۔ ملک کی معاشی صورت حال کو کافی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ میڈم ہندوستان جتنی چائے پیدا کرتا ہے اس کا تقریباً ۶۵ فیصد حصہ ہم سوویت یونین کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ لیکن وہاں جو حالات پیدا ہوئے اور وہاں جس طرح سے ڈسٹربینس ہوا اس سے گزشتہ سال میں ہماری چائے کی صنعت پر بھی اس کا کافی بُرا اثر پڑا ہے اور اس ایکسپورٹ میں بڑی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اب ہم اور بھی دوسرے ممالک کو چائے دیتے ہیں۔ مثال کے لئے ہم ایران کو بھی چائے بھیجتے ہیں اور ان بہت سی جگہوں پر چائے بیچ رہے ہیں لیکن جیسا کہ ابھی ہمارے معزز ممبر امین صاحب نے فرمایا کہ ہمارا چائے کی صنعت میں پہلا نمبر تھا اور

لیکن اندرونی طور پہ ہم کسی پرابلم کا شکار ہیں۔ ذرا سا اس کا بھی ذکر ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ آسام میں اور خاص طور پہ آسام میں جس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ آپ انہیں علیحدگی پسندی کی تحریکیں کہہ لیں۔ انتہا پسندی کی تحریکیں کہہ لیں یا ڈیولپمنٹ یا انصاف کے نام سے تحریکیں چل رہی ہیں اس سے بلاشبہ چائے کی صنعت پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے معزز ممبر [illegible] صاحب نے فرمایا کہ لیبر کی حالت بہت خراب ہے تو یہ بہت پرانی کہانی ہے جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اس ملک میں کیا کسی بھی ملک کے اندر جب تک سرمایہ دار اور ورکنگ کلاس رہے گی۔ انہیں یہ شکایت رہے گی۔ چاہے وہ گجرات کی انڈسٹری ہو۔ چاہے وہ آسام کے چائے کے باغات ہوں یا اترپردیش کی زمینوں پہ کام کرنے والے مزدور ہوں۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ ان کی حالت خراب ہے اور عورتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ بچوں سے کام لیا جاتا ہے لیکن ایک بہت اہم بات کہ آخر آج یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی۔ کیوں کہ بہت سے باہر کے سرمایہ دار آئے۔ آسام کے اندر انہوں نے باغات خریدے ان سے پروفٹ کمایا۔ کروڑوں اربوں روپیہ کمایا۔ لیکن اسے اس جگہ انویسٹ کرنے کے بجائے۔ اس کام کو اور بڑھانے کے بجائے۔ وہ وہاں کے پروفٹ کا سرمایہ نکال کر دوسری جگہوں پر لے گئے اور وہاں لگا دیا۔ اس ملک میں کسی بھی ہندوستانی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی حصہ میں جا کر تجارت کرے لیکن [illegible] اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ تجارت کے نام پہ ایکسپلائٹیشن کرے۔ یہ آسام کے اندر ہوتا رہا ہے۔ میڈم ہمارا ٹارگیٹ [illegible] ملین کلوگرام کا اس سال کا ہے۔ مگر ہم اسے پروڈکشن وائز دیکھیں تو ہم کم سے کم نو دس فیصدی کم پروڈکشن کر پا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف پروڈکشن کم نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ کوالٹی بھی ہم مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس میں گراوٹ آ رہی ہے اور وہ اس لئے آ رہی ہے کہ مینجمنٹ جو عموماً باہر کا ہے وہ انٹیریر علاقوں میں جا کر کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ خطرہ محسوس کر رہا ہے سیکیورٹی کے کارن اور جو سستی لیبر ہے وہ پروڈکشن کو اس طریقہ سے نہیں کر پاتی جو ایکسپرٹیس کی ضرورت ہے۔ وہ اس میں استعمال نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس وقت

پیسہ انویسٹ کئے ہوتے ہیں وہ یقیناً وہاں سے پیسہ نکال کر اور دوسری جگہوں پر لے جانے کی کوشش کریں گے اور وقت اپنے ان باغات اور انڈسٹری کو بیچنے کی کوشش کریں گے۔

میڈم، یہ الزام لگایا جاتا ہے حکومت اس بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہوگی کہ گزشتہ کچھ ہفتوں اور مہینوں کے اندر ٹی اسٹیٹس کے جو مالکان ہیں ان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی اور دو لاکھ سے پندرہ لاکھ بیس لاکھ تک جمع کرانے کی ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو کہا گیا اور بعض لوگوں نے پیسہ جمع بھی کرایا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں لیکن یہ ثبوت پر نہیں ہے۔ اس میں خالی لیبر کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کا مسئلہ بھی ہے جب ایک بزنس مین بزنس کرنے کے لئے جاتا ہے تو ہمیں بالکل ہی اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے کہ وہ لوٹ کھسوٹ کرنے جا رہا ہے جب وہ اپنا سرمایہ نکال کر لے جاتا ہے انڈسٹری سک ہوتی ہے یا دوسرے طریقوں سے وہ سک بنا دیتے ہیں تو الٹی بیٹھتی، اس کا نقصان حکومت اور ملک کو اٹھانا پڑتا ہے جیسا کہ ابھی چائے کمپنیوں کو حکومت کو لینا پڑا۔ سک انڈسٹری ہونے کی وجہ سے اور اس سلسلہ

پتی کو توڑ لیا ہے۔ اس کے تین دن بعد وہ توڑتی ہے اس پتے کی کوالٹی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو جس طرح بلیک کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا جس کے نتیجے سے کبھی کبھی دو روپے سے چار روپے تک فرق پڑ جاتا ہے اور کروڑوں روپے کا نقصان اس سے ہوتا ہے۔

میڈم گزشتہ سال آسام میں مسٹر سریندر پال جو سوراج پال کے بھائی تھے ان کا دھمکی میں قتل ہوا اور اس کے بعد لیٹن اور جو دوسری کمپنیاں ہیں جن کے مالکان رات اپنے اسٹاف کو ائیر لفٹ کیا۔ اب وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب مینجمنٹ کی جو دلچسپی ہے وہاں کم ہو جائے گی تو اس کا برا اثر پڑے گا میڈم مجھے خطرہ ہے کہ کل یہاں جس طرح ذکر ہو رہا تھا۔ تب بھی یہ بات سامنے آتی تھی کہ جس طرح پنجاب سے لوگ وہاں کی سیکیورٹی کی پرابلم کی وجہ سے اپنا سرمایہ نکال کر ملک کے دوسرے حصوں میں لے جا رہے ہیں جس کے نتیجہ میں پنجاب کی جو معاشی حالت ہے اس پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح پورا اندیشہ ہے کہ اگر آسام کے حالات پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی گئی تو چائے کے باغات میں جو لوگ

میں ایک بڑی رقم ادا کرنی پڑی۔ میڈم
ابھی امین صاحب نے بڑا صحیح سوال
اٹھایا کہ آپ نے سک انڈسٹری ڈکلیئر تو کر
دی لیکن ان کو سزا کیا مقرر کی۔ سزا تو آپ
کچھ مقرر کرتے نہیں ہیں۔

میڈم، اس پرابلم پہ کوئی خاص طور پہ
میرے پاس کوئی سجھاؤ نہیں ہے لیکن جو
موٹے موٹے سجھاؤ میرے ذہن میں آتے
ہیں وہ میں محترم وزیر تجارت کے سامنے
رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اس پہ توجہ فرمائیں
اور یہ دیکھیں کہ چائے کے ایکسپورٹ کو
ہم کس طرح بڑھا سکیں، چائے کے پروڈکشن
کو ہم کس طرح بڑھا سکیں۔ نہ صرف چائے
کے پروڈکشن اور ایکسپورٹ کو ہم بڑھا سکیں
بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کر سکیں۔
میرا خیال ہے کہ آسام میں جو حالات پیدا
ہوگئے ہیں، خاص طور سے چونکہ بہت بڑی
تعداد میں ہم چائے وہاں پیدا کرتے ہیں
وہاں یہ احساس ڈیولپ ہو گیا ہے آسام
کے عوام کے ذہن میں کہ باہر کے لوگ یہاں
آتے ہیں۔ ہمارے چائے کے باغوں سے منافع
چائے نکال کر لے جاتے ہیں اور پرافٹ
خود کما کر دوسری جگہ اس کو انویسٹ کر
دیتے ہیں اور ہمارا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت
اس بات کی ہے کہ پارٹیسپیشن منیجمنٹ میں
زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جائے
تبھی یہ کچھ تھوڑی بہت نفرت کم ہو سکتی
ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چائے کے کچھ مالکان
ہیں جو ڈرتے ہیں۔ کئی بار لیبر صحیح کام نہیں
کرتی اور وہ ان سے کام بھی نہیں لے پاتے
اس لئے کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ لیبر کے
کسی لیڈر کا تعلق وہاں کسی علیحدگی پسند
تحریک سے تو نہیں ہے، کسی انتہا پسند
تحریک سے تو نہیں ہے۔ کنٹرول ہونا چاہئے
لیبر پہ منیجمنٹ کا جو ختم ہو گیا ہے۔ وہیں لیبر
کا بھی منیجمنٹ پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چائے کی صنعت
کو بہتر بنانے کے لئے لیبر اور منیجمنٹ کا ایک
ایسا ماحول تیار کیا جائے جس میں لیبر
یہ محسوس کرے کہ اس کا پارٹیسپیشن ہے۔
چاہے کو آپریٹو کے ذریعہ سے کیا جائے یا
اور کسی طریقہ سے ڈھونڈا جائے لیکن جب
تک لیبر کا پارٹیسپیشن نہیں بڑھے گا ان کی
حالت درست نہیں ہوگی۔ ان کا یہ احساس
جو بڑی حد تک صحیح احساس ہے کہ دوسرے
لوگ آکر کے یہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں
کم نہیں ہوگا۔ آسام کا مسئلہ صرف چائے کی
انڈسٹری سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ غیر ملکیوں
کا مسئلہ بھی یہاں پہ بہت بار اٹھتا رہا ہے۔

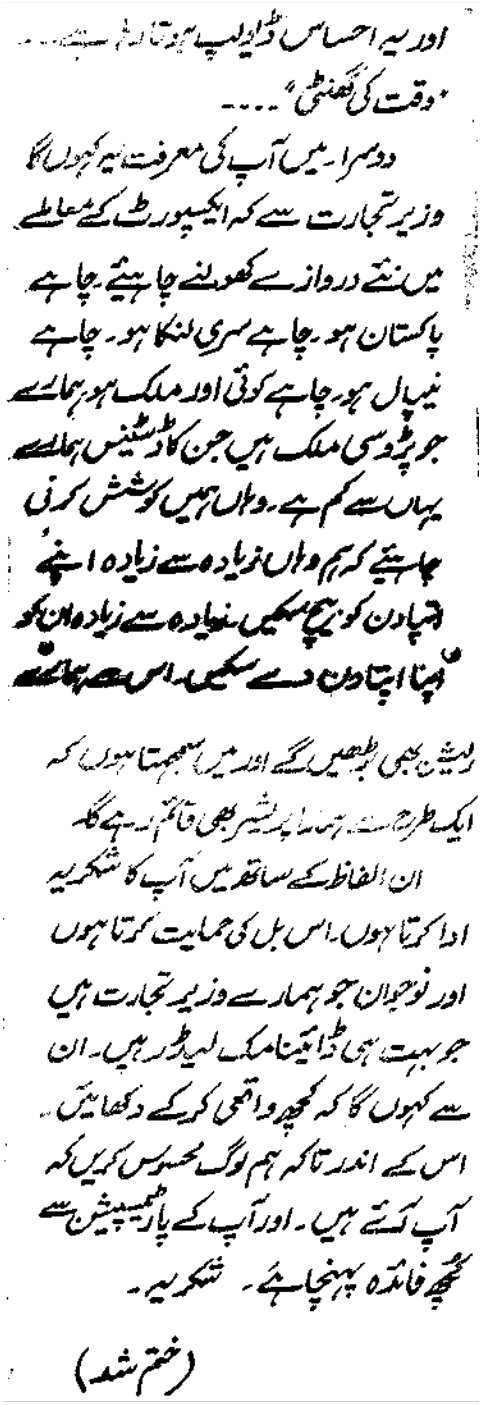

اور یہ احساس ڈیولپ ہوتا رہتا ہے [illegible]
"وقت کی گھنٹی" ....

دوسرا۔ میں آپ کی معرفت یہ کہوں گا
وزیر تجارت سے کہ ایکسپورٹ کے معاملے
میں نئے دروازے کھولنے چاہیئے۔ چاہے
پاکستان ہو۔ چاہے سری لنکا ہو۔ چاہے
نیپال ہو۔ چاہے کوئی اور ملک ہو۔ ہمارے
جو پڑوسی ملک ہیں جن کا ڈسٹینس ہمارے
یہاں سے کم ہے۔ وہاں ہمیں کوشش کرنی
چاہیئے کہ ہم وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے
اتپادن کو بیچ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کو
اپنا اتپادن دے سکیں۔ اس سے ہمارے
ریلیشن بھی بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ
ایک طرح سے ہمارا پرسٹیج بھی قائم رہے گا
ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ
ادا کرتا ہوں۔ اس بل کی حمایت کرتا ہوں
اور نوجوان جو ہمارے وزیر تجارت ہیں
جو بہت ہی ڈائینامک لیڈر ہیں۔ ان
سے کہوں گا کہ کچھ واقعی کر کے دکھائیں۔
اس کے اندر تاکہ ہم لوگ محسوس کریں کہ
آپ آئے ہیں۔ اور آپ کے پارٹیسپیشن سے
کچھ فائدہ پہنچا ہے۔ شکریہ۔

(ختم شد)

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam Vice-Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill, the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Amendment Bill, 1991. As such the Bill is a very simple Bill because it provides only for giving payment of a claim of Rs. 1,26,33,622 only to category 1 workers. I believe this could have covered many more workers and if the Bill had also included about improvement in the tea units acquired by this tea company, the Bill would have been more meaningful. In the Statement of Objects and Reasons it says, "Due to prolonged disturbance in the area and disruption in the normal working of the sick units....". These units basically are one in Karimganj in Assam, one in Jalpaiguri in West Bengal and three in Darjeeling. I don't think during all these years there was any prolonged disturbance as such or was there large-scale absenteeism for which the Government is trying to put the blame on the 3285 employees. In fact, it is the management itself which was responsible. So the reasons given in the Statement of Object and Reasons, I don't think, are properly given.

Coming to this Tea Trading Corporation of India, the above company was formed about twenty years ago. There are now five tea estates taken over by the Government. During the last fifteen years the compaay has been making losses. Ever since it started functioning, except in 1985-86 when it made a marginal profit of Rs. 30 lakhs, the total loss incurred by it is Rs. 11.30 crores and the result is the entire liquity is gone. It does not appear that this com-pany can ever make profits the present management and the present system continues. If we look into the records, we will find that the company has neither increased its profits nor the quality of tea has been improved. The company at present owns all the five tea estates. The transfer of ownership has been done only recently. Previously, it was under the control of acquisition law. In

spite of the transfer, there is no visible improvement as far as capital input is concerned. The machines are obsolete and the company requires more than Rs 500 lakhs for improving this position. It is only When the management is changed and they have a more competent management to manage the affairs of the company that the position can improve. The company has been making losses every year since 1981. The losses that have been reported so far are something like this: Rs. 41 lakhs, Rs. 218 lakhs, Rs. 346 lakhs, Rs. 539 lakhs and Rs. 210 lakhs. A profit of Rs. 32 lakhs was made in the year 1986. In 1987 it was Rs. 268 lakhs and in 1988 it was Rs. 161 lakhs. What I am trying to impress upon the hon. Minister through you, Madam, is that the company has never faced a situation like this in the last ten years. This company has been making losses continuously. The company was essentially set up for the purpose of improving India's export of tea and trading was its main focus of attention. But in the course of time Government took over some 60 gardens in pursuit of social objectives. I do not know if any social objective has been achieved by taking over this company other than draining away the hard earned resources of the country. A separate division for maintaining the gardens was also started. In spite of the separate division, the accountability aspect was ignored and as a result we could not get what was expected. Some time back the Chairman whom I met, said that the machines that are being used are obsolete machines and that they had not been changed for the last ten years. In fact tea industry is one industry where technology is fast improving and we don't have to import this technology. It is there in the country itself. By applying these new techniques and using new machinery we could have improved the quality and quantity of production. There is another matter of great concern, that is, 3 lakh chests of tea are lying in the warehouses. Three lakh chests of tea are just lying in the warehouses without being taken care of. Since tea is a perishable commodity, the entire quantity of tea would go waste. Madam, you will be surprised to know that 55,732 kgs of tea are lying in different warehouses and this tea has been valued at Rs. 1 per kg. I wish all this 55 kg of tea could be distributed to the poor people or the poor parliamentarians at rupee one per kg so that we can drink tea for some more time at the price that they have valued it. Madam, I have never heard of a disposable sweeping tea in the tea industry until now. I too hare some experience with the tea industry but I have never heard of any-sweeping tea so far. I believe there-is something wrong. It is not sweeping tea but it is being sold as sweeping tea in the interest of a few-people. There is some vested interest here. Again, Madam, there is no revival programme for the organisation. It was expected that there would be a revival programme for the organisation once a permanent managing director is appointed. But now there is a managing director and there is no revival plan as yet. The Chairman of TTCI has himself suggested that the company should be wound up. And, Madam he has mentioned—I am quoting—"We have to consider really the alternative." This is the Chairman'? view. In view of all these things, and if we consider the tea industry as a .whole in the country, I think in the entire country the worst-managed tea organization is the TCI. If they do not pay to the workers, if they do net pay to the creditors and if they continue to make losses, it is entirely their own problem and it is their own da-ing.

Madam, coming now to the tea industry in general, I would like to mention that the tea industry as such is one of the most important foreign exchange earners for our country. We should also remember that tea is are an agro-based industry which is em

[Shri Santosh Bagrodia] ployment-oriented and which earns foreign exchange for us. But, because of mismanagement in the entire tea industry and because of the wrong Government policies, what is happening is that in the tea exports also, while we were first in the world once and came down to the second position, now we are the third in the world. This is the position, if we just see the records. Our honourable Minister has said one of these days that the global share of Chinese tea in 1980 was 12.5 per cent which increased to 14.27 per cent in 1985 and 16.77 per cent in 1990 whereas India's share, which was 26 per cent in 1980 and 22 per cent in 1985, came down to just 13 per cent in 1990! And, if this situation continues, I do not know where we are going to land finally. While I appreciate the honourable Minsiter's stand that we should not export from our production, I would like to state that a new emphasis is being laid on this that we must produce for exports and, for that, quality is very essential, a very essential criterion, because, unless we produce quality products, we will not be able to compete with the ether countries at all. For the last so many years, our exports have be m stagnant and stagnancy is there at 200 million kgs. This year I do not really know whether we will be able to export even this much because of the Russian problem. Mr Minister you think we will be able to export?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam, I would like to mention that both in our production and in exports we are well on our target and there should be no problem on exports at all.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, if the honourable Minister feels that there will be no problem on exports, I will be very happy, because whatever I have said is based on whatever information I have been getting and I will stand corrected in case we reach the target of 200 million kgs. this year also. I think the target is 215 million kgs.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes. But the target is 210 million kgs.

SHRI SANTOSH BAGRODIA; Madam, 600 million cups of tea is being drunk in the country and tea is one of the commodities which are supposed to be the cheapest in the world. If we do not add sugar and milk and if we consider tea only and take tea as black tea, that is the cheapest drink in the world and six hundred million cups of tea is being consumed and the poorest of the poor are taking tea for their energy. If the tea industry is not taken care of, I am sure a day will come when it will be a great problem even for the poor to get their tea. During the last few years, only a 50 per cent increase has *been* there in the area whereas production has increased during the last forty years from 250 million kgs. to 750 million kgs. This is because of better productivity. If you increase the area also, I am sure India can definitely be a leader in the world production of tea and tea exports.

Madam, in the connection, I would like to give a few suggestions to the honourable Minister for his kind consideration, if he wants.

One of the most important factors in the tea industry which is coming in the way is the sale of tea by auction, By selling tea in the auction, the entire market is controlled only two multinational companies, that is, M/s Brooke-Bond and Lip-tons. Nobody else is buying and nobody can buy and, if they are in the market, they will buy and they will control and if they withdraw from the market, if they withdraw from the auction, then the prices will come down. They play with the entire tea industry of the country. I want to warn the hon. Minister. Kind ly look into it more seriously. This is the only commodity, Madam, in

the world which the industry or the manufacturers are supposed to sell of in auction. No other commodity is supposed to be sold in auction. Why should they be forced to sell it in auction? I can't understand. Let them produce the best quality. Let them sell it in the market, competitive market, in the best manner they like. Why should they give all the material to auction? This rule is there for the last so many years. It was introduced long before for a different reason. It is just continuing because probably nobody has the time to look into it. Why is it continuing even today without a valid reason?

Madam, this is the highest taxed agro industry or industry in the country. The taxation in the tea industry, over and above corporate tax, includes income tax. It is very righ-ly taxed. At least whatever profits are made, if they are re-employed in the industry, these should be deducted from the profits. That is the only way in which most of the profits can be re-employed. It will also help the country. No black money will be made. Otherwise the tea producers because of high taxation are nearly forced to make as much unaccounted money as possible.

Madam, another problem, as my friend on the other side just now mentioned, is that tea is covered into vast areas. It is not in closed walls. And security is a big problem—security to staff and workers. Particularly in todays terrorist conditions in the country and particularly in some States, in Assam and also in some parts of Darjeeling and West Bengal, it is impossible for the tea gardens themselves to arrange for all the security for their staff. And if the staff and workers are not secure, I am sure you will appreciate that they will not have the heart to work for the organization. In the process the production and the quality of tea is going down. I appeal to the hon. Minister to discuss with his other colleagues and find out a way so that the tea garden workers and staff are fully secure and they have a feeling of security in their minds. Otherwise good tea garden managers are just leaving the areas and are going to some other places for a different employment. We are losing good staff in the process.

Madam, I warn the hon. Minister that time might come when we will have to import tea. Even last year there was some move—and this move was again by people of multinational companies, Lipton and Brooke Bond —that some tea should be imported. This will be the worst thing for the country when instead of exporting tea we import it.

Madam, the Tea Board is one institute which is becoming too bulky. It is becoming as inefficient as our Food Corporation of India. This must be looked into. If necessary, We should have more decentralisation of powers of Tea Board. Otherwise instead of helping the tea industry, it is coming in the way of development of the tea industry in many areas.

Madam, we have a total of about 13,570 tea estates in the country, whereas 145 tea estates are even sick. I would like to know, what is the kind of planning, what is the plan of the Government, to revive these 145 sick tea estates? It will help not only create more employment opportunities for the workers but will also help the country to earn more foreign exchange.

Madam, this year when we talk about targets for exports—I was corrected—the target for production itself was 735 million kgs., whereas the actual production probably will not come to 726 million kgs. And this is because of various conditions on which probably the Government does

[Shri Santosh Bagrodia]

not have control. I am not trying to put the blame. It cannot be because of weather condition. Particularly in Assam the weather condition was not very good. But the target itself was kept very low. In fact, this year we could have produced even 760 million kgs. But it is only because the workers, the man. agers and the staff do not have the heart, and they are not able to work really because of insecurity. Madam, when we talk of sickness of 145 tea gardens, the sickness would not go unless the factors causing the sickness are tackled and removed. And the factors causing the sickness are not only management but also various other factors. Of course, management is one among them. I request the hon. Minister to look into the causes seriously, and try to remove all those causes if he wants, if the Ministry wants that all these 145 sick tea gardens should be revived. Madam, we must also remember that tea as a commodity is one of the top foreign exchange earners of our country. It is not an issue of South or North where it is grown; it is a national issue affecting the economy of the country and we should be very serious about it.

Madam, the rate of growth of production is only 3.8 per cent whereas the domestic consumption itself is increasing by 4.8 per cent. And the result will be that we will not be left with any tea for exports. For this, I want to know, what kind of planning our hon. Minister is making So that we have enought production left for export also.

With these words, Madam, I thank you.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Madam, thank you very much for giving *me* this opportunity to speak.

Madam, this Amending Bill is brought with a view to amending Section 16 of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea. Units) Act, 1985, Para 2 of the Statement of objects of the Bill reads as follows:

> "2. The claims received within the period specified under section 16 of the Act are being processed by the Commissioner. Howwever, due to prolonged disturbances in the area and disruption i_n the normal workig of the sick tea unites and large scale absenteeism of the staff, the claims of 3,285 employees and ex-employees of the nationalised sick tea units were received through TTCI...and a total sum of Rs. 1,28,33622 is involved..."

I would like to know that when there are 750 tea gardens in Assam covering an area of 2,2000 hee-ares producing 790 lakh kgs. of against the target of 875 lak when the production is more that target, how could it be said that are sick units. So far as the question of some companies is concerned, they^ may be sick. But it is not that on the whole we are having loss in production and also loss in the market. As against this higher production, the rate of export particularly has gone down. It was 26 per cent of the international market in 1985, and it has been reduced to 16 per cent in 1990. So, there may be some laxity in administration, may be on the past of the Tea Board or the owners. Or it may have been overlooked by the Government also.

Madam, these particular tea gardens involve the employment of 4,10,008 persons. The hon. Minister has stated in the,Statement of Objects that only 3,285 employees preferred their claims involving Rs. 1 crore and odd. So, there may be some more sick units to be taken over by the Government. In that case the claims of the existing employees or ex-employees must not have been received by the Commissioner which needs a particular time limit to be extended. So far as

ers are employed on casual wages. They art removed whenever the owner likes. Therefore, there is exploitation on the part of the owners. They are not given benefits. There is no hospital in tea garden and in the companies also. The labourers are not given benefits like provident fund, gratuity, etc. Therefore, there is some frustration in Assam. My friend Mr. Santosh Bagrodia has stated that because of disturbance, the owners are not in a position to visit their particular tea estates. Thereby also there are chances of loss. But the losses are on paper. I don't think there is any loss in production. The hon. Ministtr may clarify this. The Tea Board always shows loss. They have been subsidised by the Government. So far as I know the Tea Board has no accountability. They don't implement laws. They don't implement rules and regulations. Therefore, no accountability is seen and they are quite negligent. In all there are eight Advisory Boards but of no use. They have neither shown any interest in production nor in export. Therefore, there must be some accountability on the part of the boards which they don't have at present. By acquisition labourers are going to suffer a lot. May I know from the Minister whether there is any plan to solve the unemployment problem which is going to be created? Are they planning something which would benefit the employees and labourers? Under the Acquisition Law the companies are going to claim more and more amount and ultimately litigation will folow. It is going to happen like this. Therefore, something should be observed. It is the policy of the BJP that the Government should not indulge in trade and commerce, I would like to know, by taking over these sick units how this Government is going to handle them and in what manner.

SHRIMATI BASANTI SARMA (Assam)': Thank you, Madam. I rise in support of The Tea Oompanits (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Amendment Bill, 1991. Tea is a beverage taken by almost all sections of the society and forms an inseparable part of our State economy, It is a major industry earning a hugs amount of foreign exchange and employing nearabout 40 per cent of the population of the State of Assam.

But I feel sad to say that recently a stagnancy has been observed in its production and some tea estate are on the verge of closing down. So, in. this connection, it would be better for the Government to take up the sick units and look into the causes of their sickness and tackle it effectively.

At present, the production of tea per hectare is 15,000 kgs. per annum. But it can be multiplied by introduel ing modern knowhow, mechanisation and by using fertilizers it can boost tea production.

The Government should also look into tht social security of the workers, whether it is in the private or the public sector.

Then, the security of the employees and the interest of the workers must eb protected by the Government by honouring the agreements with the trade unions so that modern facilities like water supply electricity and schooling and good dwelling places could be extended to the tea garden workers.

Last of all, I would request the Government to shift the headquarters from Calcutta to Assam. With these words, I support the Bill.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : (आन्ध्र प्रदेश) : वाइस चेयरमैन साहिबा, यह जो कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर आफ सिक टी यूनिटस) एमेन्डमेंट बिल, 1991 है इसकी मैं भरपूर ताईद करता हूं। इसकी वजह यह है कि इस बिल के जरिये कोई 3285 मौजूदा इम्प्लाईज और एक्स-इम्प्लाईज के क्लेम्स का मसला हल होंगे । इसमें जो 1 करोड़ 28 लाख रुपयों की रकम इंवोल्व है, इसका ज्यादातर फायदा वर्किंग क्लास को होगा । इसकी वजह से मैं इसकी ताईद करता हूं । इससे इंट

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

के इस मौके का फायदा उठाते हुए यह जो चाय की सनत है, मुल्क के ताल्लुक से किस सूरतेहाल से यह सनत गुजर रही है वह मैं आपके जरिये से हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूं । जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज से कोई 40–50 साल में पूरी दुनियां में हमारा मुल्क चाय की पैदावार में सबसे अव्वल मोमालिकों में गिना जाता था और न सिर्फ चाय की पैदावार हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा होती थी बल्कि चाय की जो क्वालिटी होती थी उस क्वालिटी के ताल्लुक से भी हिन्दुस्तान की चाय पूरी दुनियां में अच्छी और अव्वल चाय समझी जाती थी ।

मगर जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया चाय की सनत मुतासिर होती गई । उसके कई वजूहात हैं । एक तो जो हमारे शमायेदार हैं, जो चाय की सनत में लग हुए हैं, उनकी कुछ कोताही और उनकी लापरवाही भी इसमें है । दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जितनी सरपरस्ती इस सनत में होनी चाहिए थी वह सरपरस्ती नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से चाय की सनत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है और आज सूरतेहाल यह है कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, पड़ौसी मुल्क हैं, बहुत छोटे मुल्क जैसे श्रीलंका है उसके बाद हिन्दुस्तान का नम्बर चाय की पैदावार में आता है ।

उसकी वजह यह है कि चाय की पैदावार में हमारे मुल्क में कमियां हैं । इस कमी की वजह से न सिर्फ हमारी तिजारत मुतासिर हुई है बल्कि उन इलाकों में जहां पर चाय की पैदावार होती है, जैसे कि आसाम है, मगरबी बंगाल है, जनब की रियासतें हैं, उन इलाकों की जो सनतें हैं, वहां की जो मइसत है, उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है । लिहाजा हुकूमत की जानिब से फौरी तवज्जह दी जानी चाहिये । खासतौर से पिछले दो-तीन सालों से चाय की पैदावार पर असम में बोडो तहरीक की वजह से असर पड़ा है । बोडो तहरीक और फिर अल्फा की सरगर्मियां, इसकी वजह से भी काफी असर पड़ा है क्योंकि असम सबसे ज्यादा चाय पैदा करने वाली रियासत है । वहां पर इस किस्म की जो तहरीकें चल रही हैं उसकी वजह से भी चाय की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है ।

दूसरी बात यह है कि अब हमें देखना यह है कि हम किस तरह से खोया हुआ मुकाम वापस ला सकते हैं । सबसे पहले चाय की पैदावार की जो अफजायश है उसकी तरफ हमको तवज्जह देनी पड़ेगी और उन नये इलाकों में जहां पर चाय की फसल की इमकानात है वहां पर चाय की फसल उगानी पड़ेगी । कई पहाड़ी इलाकें हैं हमारे मुल्क में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हैं और फिर जूतूब में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चाय की पैदावार की जा सकती है । मगर हुकूमत की तरफ से न तो कोई खास इस ताल्लुक से प्रोपेगंडा हो रहा है और न हुकूमत की तरफ से हिम्मत अफजाई हो रही है । इसकी वजह से हमारे काश्तकार इस काबिल नहीं हैं जो वे चाय की काश्त कर सकें । लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से हुकूमते हिन्द से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस तरफ तवज्जह करें ताकि चाय की पैदावार में इजाफा हो ।

तीसरी बात जो है वह यह है कि हमारे जो चाय के कारखाने हैं वे चाय के कारखाने भी बिल्कुल पुराने होकर रह गये हैं और वहां पर जो मशीनरी है वह मशीनरी इतनी पुरानी हो गयी है कि अतः वह इस काबिल नहीं रह गयी है कि मौजूदा दौर में जो बेहतरीन मशीनरी आयी है, उसका वह मुकाबला कर सके । लिहाजा हमारे इन कारखानों को असली कारखाना बनाना पड़ेगा । जब तक आप इन्हें असली कारखाना नहीं बनायेंगे और आज की मशीनों के मुकाबले, लेटेस्ट टाइम की मशीनें आप हमारे कारखानों में नहीं लायेंगे, उस वक्त तक आप चाय के मामले में इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर सकेंगे और जब इंटर नेशनल मार्केट में हमारी चाय कंपीट नहीं कर सकेगी तो जाहिर है कि सिवाय नुकसान के आप फायदे का तसव्वुर नहीं कर सकते ।

लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत से एक दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी चाय के कारखाने हैं, उन चाय के कारखानों की तरफ आप तवज्जह कीजिये और उनको लेटेस्ट टाइप की मशीनें आप मुहैया करने की कोशिश कीजिये ।

अगली बात यह है कि हमारे चाय के जो मजदूर हैं उनकी जो बुरी हालत है उसकी तरफ मैं हुकूमत की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । आजकल जो सहूलियतें मजदूरों को मिलनी चाहिये उस किस्म की सहूलियतें हमारे चाय में काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिल रही हैं और फिर चाय की सनत के जो बाविस्ता सरमायेदार हैं वे इन मजदूरों का इस्तहसाल कर रहे हैं । मर्दों को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिये, औरतों को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिये, उस किस्म की मजदूरी ये नहीं दे पा रहे हैं । फिर हुकूमत जो है उसकी गफ्लत की वजह से, हुकूमत की लापरवाही की वजह से सरमायेदारों की हिम्मत काफी बढ़ी है और वे मुस्सिल मजदूरों का इस्तहसाल करते नजर आ रहे हैं । लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमारे वे मजदूर जो चाय के खेतों में काम करते हैं, उनकी तरफ तवज्जह दी जानी चाहिये और उन मजदूरों को बेहतर सहूलियतें मिलनी चाहिये । वे तमाम सहूलियतें जो दूसरे मजदूरों को मिलती हैं उस किस्म की सहूलियतें उनको भी मिलनी चाहिये । उनको सब तरह की सहूलियतें मिलनी चाहिये, उनके बच्चों को तालीम की सहूलियतें मिलनी चाहियें । इस तरफ हुकूमत को तवज्जह बेहद जरूरी है । यह तमाम बातें हैं जिसकी वजह से हमारी चाय की सनद दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है । खास तौर पर हम यह देखते हैं कि कई ऐसी कसियां हैं जिनकी वजह से चाय की कीमत नहीं मिल रही है । मिसाल के तौर पर जिस वक्त पर फर्टिलाइजर देनी चाहिये अगर फर्टिलाइजर देने में पांच-सात रोज का फर्क पड़ जाए तो चाय की पैदावार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है । जब फसल बिलकुल तैयार हो जाती है उसको काटने में अगर एक-आध हफ्ते की देर हो जाए तो चाय की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है । लिहाजा यह कई बातें हैं जिनकी वजह से चाय की सनद गिर रही है । चाय की पैदावार आप बढ़ाइये और फिर एक्सपोर्ट प्रोमोशन के काफी अच्छे चांसेज हैं । वर्ल्ड मार्किट इस वक्त चाय की सनद के लिए खुली है । आप कम्पीटिटेव अन्दाज में आगे बढ़ते हुए इसका एक्सपोर्ट प्रोमोशन कीजिये । अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो आप यकीन मानिये आज से 30-40 साल पहले जो हमारी चाय की सनद की सूरतेहाल थी, जितनी तिजारत चाय की हम करते थे, उससे भी ज्यादा फायदा हमें हो सकेगा । इन चंद अल्फाज के साथ, आपने मुझे जो टाइम दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Shri Digvijay Singh. He is not here, Shri Buragoham. He is also not here. Now, the hon. Minister please.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Madam, at the very outset, I must record my appreciation for the concern shown by Members from both sides of the House for the welfare of the labour force working in the tea gardens of our country, as well as for the concern shown by them for con-continued impetus to export of the tea produced in the country.

I would like to point out that it is the sensitiveness and concern of this Government towards the welfare —basically, the welfare—of the working class that compelled the Government to bring this Bill before the House.

A question was raised whether there was any negligence on the part of the T.T.C.I., or, any other organisation, , in processing thesa claims. I would like to inform the House that, to the best of our knowledge. there was no negligence, or, wilful default. But thee claim could not be processed. They had to signed by the workers, or. their representatives, and they were received in three separate lots by the Claims Commis-ioner, but outside the period of limitation. Therefore, it has become

[Shri Salman Khursheed] necessary to extend the period of limitation, so that the legitimate and justified clam of the workers of these estates can be considered and adjudicated upon and the workers given their just deserts.

1 appreciate the unanimous concern of the House to assist the wor-Kers, to help the workers, and their support in passing this beneficial piece of legislation. As several Mem-bers pointed out, it is, basically, a very simple amendment, not requiring a great deal of exertion, or, explanation, from the Government. But since several issues have been raised regarding tea production as well as the conditions in which the tea gardens exist at present, specially, in the States of West Bengal and Assam, I would like to bring some points to the notice of the House.

Hon. Member, Mr. Afzal, raised the question as to what action is being taken, or, is intended to be taken, against those owners who have, by their wilful default, or, negligence, caused these tea estates to become sick. It is not the purport of this legislation, or, any other legislation, brought forward toy the Ministry of Commerce. Indeed, it is not under the jurisdiction of the Ministry of Commerce to take any punitive action, penalising any person who has, wilfully, or otherwise, caused any industry, any tea estate, to become sick. 4,00 P.M.

This is a matter of larger concern. Owners of industry and owners of any farm of industrial unit should be penalised or not, this is a matter of national debate and not the concern or within the purview within which we come today . Certainly, it is not also the intention of this Government to police, to indulge in police activities in areas of com-merve. On several occasion it has bees? made clear by the Minister of Cowmerce that the purpose of the Ministry of Commerce is to provide all possible, reasonable, rotional assistance to the exporting community, to organise in those areas of produc. tion which is related to export and to give all possible impetus to greater export from this country. Towards that, in this context it is important for this House to know that subst-antial effort is being made in the research and development area for increasing productivity of tea. The Tea Research Association which was previously partly financed by the Indian Institute of Agricultural Research and partly by the Ministry of Commerce has now been brougt under the Ministry of Commerce for more comprehensive research effort. The House will be pleased to know that high-yield-ing variety of tea has also been found. which can provide 6000 kgs per hectare of tea plantation. Research and development is an important part of our total effort in giving impetus to tea plantation and tea export.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Just a second, Mr. Minister. This 6000 kg. variety, I would like to know where it is available, whether you have offered to the industry or it is just in the initial stage.

SHRI SALMAN [KHURSHEED: The variety has been identified. It is yet to be planted. Hon. Member's speech indicated his intense knowledge of the tea industry. He must be aware that it takes time for the bushes to be developed. Then it takes time for the bushes to be planted and the bushes then become mature to provide tea. I would only say that this variety has been identified. It is a very major step. We are not out of tune with the averages in the world of tea production. The average productivity across the country in India is 1627 kgs. per hectare, whereas in Sri Lanka it is 963, Indonesia has 1039 and "Kenya which is the highest and they have done very well over the last five to ten years has 1824 kgs.

Even on the price and quality of tea some questions were raised, aboul the quality of tea falling in the country. I do not say that the tea

is of the same quality everywhere, nor can it be of the same quality everywhere but as against the very high price of Chinese tea, we also have a smalli patch though of a gar. den and that particular patch has fetched as high a price as Rs. 5000/-per kg. Of course, that is only an exceptional paich, but if is only to emphasize that the quality of tea in our country is not something that we should overtly be pessimistic about. Efforts are being made constantly to ensure that both be quality and the productivity regain. of the highest standard.

Questions have been raised, Madam, regarding lobbies in tea, related also to the lack of effort by the various owners of tea estates in increasing production, in ensuring that the labour force is given good conditions. A question was also raised on whether TTCI has any plans to/ nurse itself back to health and then to nurse the 145 sick units back to health and why we are no longer a major exporter. Hon. Santosh Kumar has raised this issue and I would like to say that although we are not now the first amongst the exporting countries in the world, we still remain a major exporter. It should be clarified that Sri Lanka, in production, has a share of only 9.06 per cent of the world production as against India's 27.79 per cent—28per cent approximately—of the world production and against China's 22 per cent of the world production. So, in terms of world production we still remain the major producing country. But in terms of export I accept, regrettably, that we are no longer the first of the exporting countries in the world.

Honourable Members themselves, I think, are fully aware that consumption of tea is going up. Honourable Members themselves contribute great. ly to the consumption of tea in the Iobbie-3 of Parliament. While on the one hand we speak in lobbies on tea we also speak, on the other, of. tea in the lobbq. I would only say that it can not be upon our shoulders Ho discourage the consumption of the, although that may well be one of our concerns. So, where we cannot discourage the consumption of tea, we have to do whatever is possible to ensure that productivity of tea goes up and, for thig purpose, we have made considerable effort to ensure that there is nothing lacking towards productivity and the increase of productivity, and several very important schemes have been already put into motion. Over the next ten-year period we have a target of reaching 1,000 million kilogrammes of tea, for which purpose we have several schemes which I would outline for the information of honourable Members of the House.

(1) There is a Tea Plantation Finance Scheme which is the Tea -Board's loan for replanting, extension planting as well as replenishment planting of existing tea estates. (2) There is a Tea Machinery and Irrigation Equipment Hire-Purchase Scheme, again of the Tea Board, where loans are provided for irrigation equipment, etc. (3) The Tea Replantation Subsidy Scheme for replacing of old bushes. As the honourable Member from this side of the floor has said, many of the tea bushes are over 50 years old. The rate of subsidy provided is Rs. 10,400 per hectare for gardens in the plains, Rs 12,400 per hectare for garden in the hills and Rs. 15,000 per hectare for gardens in Darjeeling. (4) The Tea Area Rejuvenation and Consolidation Scheme which provides subsidies fo-r rejuvenation, pruning and in-filling where the bushes are thin. (5) New Tea Unit Financing Scheme whereby special loans and subsidies arp granted for extending tea> Cultivation in the non-traditional areas. (6) Darjeeling Interest, Subsidy Scheme, which is a special scheme for the revival of Darjeeling gardens for reasons ...best know "a to this House. Darjeeling had suffered considerably-during the-agi. tation there, and where the gar-dens

[Shri Salman Khursheed] were languishing on acount of this and the production cost being high, special interest subsidy is provided for that area. (7) Scheme for interest subsidy on bank loans for irrigation and drainage at the rate of four per cent is provided across the board. (8) Scheme of interest subsi. dy on extension planting at the rate of three per cent across the board. This is as far as the increase of production incentives is concerned.

Honourable Members have raised the issue of why other areas cannot be identified for extension to non-traditional areas. Uttar Pradesh was one such area mentioned. I would like to take honourable Members into confidence to say that Uttar Pradesh, in fact, was the area which first saw plantations of tea in this country over a hundred years ago. Unfortunately, the few tea estates that are left in Uttar Pradesh, although producing a very high quality tea, do not have a high level of productivity and, therefore, substantial effort needs to be put into those gardens, and we have also to consider nether other areas of Uttar Pradesh could be brought under tea plantation . I myself will be visiting the Uttar Pradesh tea-growing areas as well as the capital city of Lucknow . to discuss with the State authorities as to what we can do regarding implementation of schemes that have been prepared for the development of tea production in the Uttar Pradesh area.

The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair; Sir, the hon. Member, Mr. Mohammed Amin, also raised question on violations, and I think some others also are equally concerned about violations of labour laws, violations of provident fund laws and violations of other local laws of the country. It is not, again I repeat, under the purview of the Commerce Ministry to enforce every such law. Every law has an implementing and sanctioning authority. If it is brouj to our notice that laws, specia those relating to labour, are not f lowed, specially in the gardens are under the purview of the TTO we would take the utmost steps are necessary to ensure that just is done.

SHRI MOHAMMED AMIN: purpose of my making the point that since you are a member of Council of Ministers, you can br: it to the notice of the Cabinet that the Government can brin comprehensive legislation.

SHRI SALMAN KHURSHEED: shall certainly convey the cone of the hon. Member on this issi The provident fund issue is also fore us, specially in those four g dens regarding which this partict legislation has come from this Hot No other outstanding claim has cc to our notice. If any such claim act of violation of law is brought our notice by an hon. Member, would be happy to take them stringent steps in that direction.

As far as the actual sickness of tea estates is concerned, we h made efforts to identify the reas for the sickness. The reasons for sicknes, have been identified to elude, amongst other things, indi rent management, availability of adequate finance for investment. ' Tea Board has been advised to the owners of such sick gardens gether so that it can be sugge; to them and they can be asked vs assistance they may need in orde get these gardens going. Incent: also are necessary, and incent: have been provided under the tax so that the money that is ear from these tea gardens can be re ployed back into the tea gardens nurse them to greater health.

As far as the TTCL is concen the health of the TTCL is also major concern of Ministry of C merce. We have appointed con

tants, and a report has already been received and it is under consideration.

Various suggestions have been made regarding what can be done with the TTCL. Regrettably the TTCL did' not have a head for a very longtime. As an hon. Member from this side of the floor mentioned, the Managing Director has taken oyer barely five months ago after this Government came to power, and the Managing Director is doing his best to put the TTCL on an even wicket.

The hon. Member from the BJP Mr. Solanki, mentioned that is the BJP policy that the Government should not indulge in trade and commerce. That is a policy that this Government has already announced that so far as possible, where public interest does not require it, the Government should not involve themselves in trade and commerce. That is the reason why we cannot give an easy answer to those Members who ask us about what we will da about the 145 sick gardens. We do not have a simple answer saying that we will nationalise the 145 sick gardens. Perhaps, it is a more difficult task to have to nurse them back to health without taking over complete control by way of nationalisation. But this Government is dedicated to working hard to nursing the industry back to health without having to introduce greater regulation and greater con_ trol because this Government is convinced that human beings do respond to rational incentives and that human beings do believe in what is good for them and what is not good for them, and that the aggregate of beliefs of human beings is to be found in the market place.

We would also like to reiterate that some of the fluctuations in the production- have been caused due to prolong turbulence, whether weather. turbulence or political turbulence, in the States of West Berigal and Assam.

So far as police assistance and administrative assistance is concerned, the Home Minister has already announced in both the Houses that stringent steps have been taken to provide protection to both the employees and the management of tea estates in the State of Assam. But, along with that, I do believe and I think that this House will believe that the people of this country, the management and the owners of the tea estates of this country are not so timoroug and scared that the occupational hazards of having to work in difficult political conditions will force them to desert those estates, those properties that they have had for several generations. I do believe that we have faith in the strength of the Indian people, who withstand passing fluctuations.

If I may return to the apprehension expressed by Santosh Ji that this year we may not be able to meet the targets both of exports and of production, I shall like to reiterate again that the production up to September, for which figures are available, was up by 23 million kg as compared to last year and we are confident that it will exceed at the end of the year 735 million kg. The export target for 1991-92 is 210 million kg. at the value of Rs. 12000 awes as compared to 199 billion kg. at a value of Rs. 1,045 crores in 1991 . and till date we are more or less keeping on target. The effort of the hon. Member to push up from 210 million kg to a target of 215 million kg. is welcome. I do hope that we will reach upto his expectations, but the target that we have fixed for ourselves is 210 kg.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You have not spoken on the compulsory auctioning.

SHRI SALMAN KHURSHEED: The hon. Member is very keen on my saying something on the compulsory auction scheme. Historically tea and coffee have been treated quite differently from other cemmoditiea in this country. As the hon Member knows

(Shri Salman Khursheed)

and this House knows and as questions have been raised whether the polling system in coffee, by which all producers pool their coffee" together and then auction takes place, is an adequately rewarding system or not, I may point out such matters whether i is permissible or not and whether it is ultra vires are pending before the Supreme Court. Similarly, historically tea auctions both in London and in Calcutta had been the basis of tea trade in this country, but the entire tea production was not mandated for auction. It was only a particular percentoge which was mandated for auction. I have myself visited tea estates and tea associations in Calcutta. This issue has never been raised so far. If the tea industry seriously feels concerned about the method by which tea sales are made—and the method by which tea trade is mandated—wt would be very happy to consult them and ask the Tea Board to consider this matter seriously.

Many Members want to know why we have not been able to do anything to improve these four gardens; and if we cannot improve these four gardens, what we can do with the other 144 gardens that are with us. As I said earlier it is not for the Ministry of Commerce to run gardens. In fact, TTCL was basically incorporated for the purpose of trading in tea and for developing the export trade in tea. It was not indcorporated for the purpose of running tea gardens. Different kind of management, different kind of expertise and different kind of commitment is required for running tea estates than for indulging in tea trode. We have proposals made from different places, including a proposal that has come to us from the Chief Minister of West Bengal suggesting that these gardens be handed over to the West Bengal Tea Development Corporation. Perhaps West Btngal has a better experience of running tea garden in the State sector than certainly the Central Government has had All these proposals are being considered very seriously in the Ministry of Commerce.

A question was raised about the accountability of tht Tea Board. I would like to assure the Members of our complete commitment to ac-eoontatalibility of any unit under the Ministry of Commerce. Accountability to the Ministry and the Govern-mtnt and ultimately accountability to the Parliament is paramount for us. If the Members feel that there has been some lacuna or some shortcoming in the functioning of the Tea Board, if - they are specially made available to us, we will certainly consider them.

At the same time, on our own initiative we have already decided that tht Tea Board needs to be decentralised. At present everyone has to run to the Tea Board Head Office, Calcutta. We are now ensuring that the local regional offices of the Tea Board will be able to dispose of most of the work.

I would have really been very pleased to accept the suggestion made in the hon. Member Mrs. Sarma's speech, to shift the Head Dffice of the Tea Board from Calcutta to Assam. But unfortunately despite it being her maiden speech, I have to stand firm and say, no. Just shifting the Tea Board office will not be the answer. The answer is to ensure that people can locally get the relief and the assistaznce that they are looking for and that relief and assistance, wt assure, will be provided by the decentralisation which is already under way in the Tea Board ... (Interruptions) Well quitt often there is a talk on decentralisation of power but there has never been a talk of shifting Delhi the capital of India to another State.

Finally, the labour welfare concerns and labour welfare measures taken by the Tea Board under the

Ministry of Commerce have called for some attention. Basically the welfare activities of the Board are classified under two major heads: one is educational and the other is general welfare. In the educational field, we provide educational stipend to the wardsi of tea garden workers who are given grants for continuing studies above the primary stage. This includes tui tion fee, hostel charges. For this purpose, a sum of Rs. 4.07 lakhs was disbursed as stipend and bokos :grant. A sum of Rs. 12,000 as Nehru wards was also issued in 1989--90.

In the general welfare front, under this scheme, assistance is given to educational institutions, hospitals, health clinics Indian Red Cross Society, St. John's Ambulance Association, etc. The scheme cover financial aid for construction of institutions, hospital buildings, health centres, expansion of educational and vocational training and specialised treatment facilities for the benefit of the tea garden workers. A scheme for financial assistance for disabled workers and their dependants has been introduced. During 1989-90, Rs. 13.42 lakhs was disbursed under this general welfare scheme.

In addition to this, there are other activities for which financial assistance is also provided which includes cases of kidney transplantation technical training in Jalpaiguri Polytechnic, scouting and guiding in West Bengal, Kerala and Tamil . Nadu, sports activities etc.

Additonal grants were also provided to St. Xavier School Darjeeling and to other schools in order to take plantation workers' children on scholarships. All this; assistance is provided either to help the plantation workers or their family members and specific arrangements to this effect have been made with the schools concerned, The welfare budget for 1991-92 the revised estimates stand at approximately Rs. 30 lakhs.

Sir that in short gives a brief summary and a bird's eye view of the activities of the Ministry of Commerce and its concerned authorities to promote the export of tea and promoting the production of tea. This Bill, as I said, is a beneficial piece of legislation incontrovertibly for the benefit and welfare of the working class of over 3000 workers of these four estates.

I command this Bill to the House to be passed unanimously.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): Now, the question is;

"That the Bill to amend the Tea companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, I move:

"That the Bill be passed"

was disbursed as stipend and books

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): Now we shall take up the Banking Regulation (Amendment) Bill, 1991.

THE BANKING REGULATION (AMENDMENT) BILL, 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): Sir, I move;

That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949,